दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 16 ▸ अंक : 5 ▸ गाजियाबाद, मई, 2020 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

आर्थिक पैकेज के साथ सुधारों की फेहरिस्त, एक तीर... P-6

उत्थान समिति द्वारा जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा है राशन

—उद्योग विहार (मई 2020)—

गाजियाबाद। उत्थान समिति द्वारा पिछले लगभग एक माह से रोज जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। रोजाना लगभग 500 लोग लाभान्वित होते हैं। उत्थान समिति के चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह ने कहा की 'यह एक ऐसा संकट का समय है की इस वक्त हमें बहुत ही सब्र से काम लेना होगा तथा सभी को मदद के लिए आगे आना होगा। ऐसी भयंकर त्रासदी के वक्त जो लोग मजबूरी में राशन ले रहे हैं हमें उनकी फोटो लेने से बचना चाहिए। यदि फोटो लेते भी हैं तो को. शिश होनी चाहिए की उनका चेहरा न आये। क्योंकि वे लोग जानबूझ कर नहीं माँग रहे हैं उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके रोज कमाने और खाने के साधन बंद हो गए हैं ऐसे में हमें उनका सम्मान करना चाहिए अन्यथा हमें उनकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करके उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। हमारी संस्था प्रशासन के सहयोग से भी यह कार्य

कर रही है और जो भी जरुरत के लिए कण्ट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करवाता है तो उसे भी हम लोग राशन उपलब्ध करवा रहे हैं।' इस कठिन समय में लोगों को सही सूचना मिल सके व उनको सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध हो सकें। इसके लिए एक फेसबुक पेज "https://www-facebook-com/LEGALI-PLHR/" बनाया गया है जिसमें गाजियाबाद प्रशासन के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों के व केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों की प्रतियां समय समय पर डाल कर लोगों को को. विद–19 के बारे में अवगत कराया जा रहा है साथ ही सभी श्रमिकों एवं उद्योगों को उनसे सम्बंधित जानकारी समय पर मुहैया कराई जा रही है।

केंद्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में किया फेरबदल, पीएमओ में तैनात हुए तीन नए आईएएस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नौकरशाही में अहम फेरबदल किया है। आईएएस, आईआरएस सहित कई संवर्ग के कुल 22 अफसरों की जिम्मेदारियां बदलीं हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय में तीन नए आईएएस अफसरों की तैनाती हुई है। अप्वाइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने शुक्रवार को नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। नियुक्ति एवं कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 1991 बैच के तमिलनाडु काडर के आईएएस एस गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। वह फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड आईटी में एडिशनल सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हैं। इसी तरह 2001 बैच के आईएएस अफसर सी श्रीधर की नियुक्ति पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर हुई है। वह लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में डिप्टी डायरेक्टर पद पर अभी कार्य कर रहे हैं। कैबिनेट सचिवालय में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत 2005 बैच के हिमाचल प्रदेश काडर के आईएएस मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर पद पर नियुक्ति मिली है।

लॉकडाउन 5.0 : यूपी से अब बिहार सहित किसी भी राज्य में आने–जाने के लिए अब नहीं होगी पास की जरूरत

—उद्योग विहार (मई 2020)—

लखनऊ। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 5.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें सबसे सुविधाजनक बात यह है कि एक जून से अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। यानी जहां अनुमति हैं, वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इसे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा। ऐसे में अब लोग यूपी से बिहार, झारखंड सहित किसी भी राज्य में आसानी से आ–जा सकेंगे। लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग एक दूर से प्रदेशों में फंसे थे। ई–पास नहीं बन पाने की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे थे ऐसे में अब लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन के बाद वे आसानी से बस या टैक्सी करके अपने घर जा सकते हैं।

ये पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी

– शादियों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

❑ ई–पास नहीं बन पाने की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे थे ऐसे में अब लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन के बाद वे आसानी से बस या टैक्सी करके अपने घर जा सकते हैं।

– अंतिम संस्कार में 20 लोग रहेंगे

–फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगी।

– यात्रा के वक्त भी मॉस्क जरूरी

– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रति. बंधित

– धार्मिक–सांस्कृतिक,राजनीतिक रैली पर पाबंदी रहेगी

ये सलाह भी पहले की तरह लागू रहेगी

65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह लागू रहेगी।

संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम ही बेहतर

गाइडलाइन में कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और साफ–सफाई की पूरी व्यवस्था हो, सेनेटाइजेशन किया जाए।

स्कूल, मेट्रो, रेस्त्रां...जानिए कब क्या खुलेगा, 8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर तीन फेज में शुरू होंगी गतिविधियां

—उद्योग विहार (मई 2020)—

नई दिल्ली। सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से गति. विधियों को शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में किन–किन गतिविधियों की इजाजत होगी और किस पर प्रतिबंध रहेगा।

फेज 1 : 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।

फेज 2 : स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।

फेज 3 : अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोना जाएगा। हालांकि, इससे पहले एक बार

स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।

नाइट कर्फ्यू का बदला समय

देश में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। हालांकि इसके लिए समय में बदलाव किया गया है। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी काम से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। लॉकडाउन 4 तक यह समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन

गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गति. विधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं।

कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंध का फैसला राज्यों पर

गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वे ऐसा कर सकेंगे।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

श्रम–जगत

02 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, मई, 2020

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING				DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES	PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/20 TO 30/09/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019	1/3/2019	1/7/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA	ZONE-II BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8625.00	10086.03	10574.06	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	9024.24	8331.00
SEMISKILLED	9487.50	11075.65	11631.46	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	9475.43	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	9949.19	*
SKILLED	10627.50	12295.73	12688.87	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	10446.65	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	10969	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11517.45	*

लॉकडाउन 5: दिल्ली में मॉल खोलने की तैयारी, केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी केजरीवाल सरकार

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को पूरा होने जा रहा है। हरियाणा, गोवा समेत कई राज्य कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अगले चरण में दिल्ली को शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल और बाजार के समय बढ़ाने को लेकर राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।

स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं: दिल्ली सरकार स्कूल–कॉलेज, सिनेमाघर अभी खोलने के पक्ष में नहीं है। सैलून खोलने पर उसके निगरानी और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने को लेकर सरकार में एकमत नहीं है। इस पर फिर चर्चा होगी। उसके बाद केंद्र को सुझाव भेजे जाएंगे। वहीं, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, अधिक छूट देने से मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी जिस पड़ाव पर कोरोना वायरस का प्रकोप है, ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए।

जिम–होटल खुलें: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, कोरोना के मामले

बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि सावंत ने राज्य में जिम और होटल खोलने की इजाजत देने की भी मांग की।

उत्तराखंड भी पक्ष में : पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है तो उत्तराखंड कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाना चाहता है। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। यह संकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं। उन्होंने कहा, लॉकडाउन में ढील की जल्दबाजी नहीं है। कर्नाटक ने भी केंद्र से जल्द स्कूल खोलने की इजाजत मांगी है।

मोदी से मिले शाह : गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्रियों के विचारों से अवगत कराया। माना जा रहा है कि अधिकतर मुख्यमंत्री लॉकडाउन जारी रहने लेकिन जनजीवन चरणबद्ध तरीके से पटरी पर लौटने के पक्ष में हैं।

हत्या के मामले में कभी सजा-ए-मौत पाने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में कभी सजा–ए–मौत पाने वाले एक व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए शुक्रवार को बरी कर दिया। मध्य प्रदेश में 2008 में दर्ज हुए हत्या के मामले में इस व्यक्ति सहित तीन लोग को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के तहत मौत की सजा सुनाई थी। बाद में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 2012 में कहा कि इस मामले में मौत की सजा सही नहीं है और तीनों को उम्रकैद की सजा सुना दी। व्यक्ति ने 2013 में उच्चतम न्यायालय में उम्रकैद की सजा सुनाने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। अपने 43 पन्ने के फैसले में न्यायमूर्ति

एस के कौल और के एम जोसफ ने कहा कि व्यक्ति को इस आधार पर हत्या सहित अन्य अपराधों का दोषी करार दिया गया कि उसके पास से मृत व्यक्ति का मोबाइल फोन मिला था, लेकिन उस मोबाइल फोन की बरामदगी अपने–आप में ही संदेह के घेरे में है। पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखना सुरक्षित/ सही नहीं होगा। अन्य कई टिप्पणियों के साथ पीठ ने व्यक्ति को हत्या के दोष से बरी कर दिया।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र

दिल्ली–एनसीआर

03 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, मई, 2020

जून में 4-5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल–डीजल के रेट कम नहीं हुए। केंद्र सरकार ने जहां एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी तो कई राज्यों ने भी पेट्रोल–डीजल पर वैट बढ़ा दिया। ऐसे में सस्ते क्रूड का आम पब्लिक को कोई लाभ नहीं मिला, अलबत्ता अब जून से महंगे पेट्रोल–डीजल के लिए तैयार रहें। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल–डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर सकती है। लॉकडाउन हटने के बाद दोनों पेट्रोलियम उत्पादों के दैनिक मूल्य का एक बार संशोधन हो सकता है।

40–50 पैसा प्रतिदिन बढ़ सकते हैं दाम

कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल–डीजल में लागत और बिक्री का अंतर पहले ही 4–5 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। ऐसे में वैश्विक कीमतों को देखते हुए घाटे को पूरा करने के लिए लगातार दो सप्ताह तक 40–50 पैसा प्रतिदिन दाम बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि, सरकार के सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल–डीजल के मूल्य को सीमा से अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लॉकडाउन 4.0 में तरह की ढील के बाद कई राज्यों ने पब्लिक और प्राईवेट ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया, जिससे फ्यूल की मांग में इजाफा हुआ। लॉकडाउन के दौरान नागालैंड, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और असम और ओडिशा में पेट्रोल–डीजल पर वैट बढ़ाया गया था, जिससे इन राज्यों में पेट्रोल–डीजल की कीमतें बढ़ गई थीं।

एक जून से यहां बढ़ेगी कीमत

मिजोरम सरकार ने 1 जून से राज्य में पेट्रोल पर 2.5 फीसदी और डीजल पर 5 फीसदी की दर से वैट बढ़ाए जाने का ऐलान किया है, जिसके बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। वहीं जम्मू–कश्मीर में पेट्रोल पर टैक्स दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। वहीं डीजल पर टैक्स में एक रुपये लीटर की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि संशोधित दरें एक जून से लागू होंगी। हिमाचल प्रदेश ने भी एक जून से डीजल और पेट्रोल पर दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था शुरू करने पर मंथन

सरकारी तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह सभी खुदरा तेल विक्रेताओं ने बैठक की। इसमें मौजूदा स्थिति का आकलन किया गया और लॉकडाउन के बाद कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था शुरू करने का रोडमैप तैयार किया है। अगर लॉकडाउन को 5वीं बार बढ़ाया जाता है, तो भी सरकार से मंजूरी लेकर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए सोच-समझकर रणनीति बनाने की जरूरत : रिपोर्ट

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। कोरोना वायरस पर काबू के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण रविवार 31 मई तक है। वहीं अब लॉकडाउन 5.0 की भी अटकलें शुरू हो गई हैं। ऐसे में भारत को वृद्धि दर में स्थिर गिरावट को रो. कने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति काफी सोच–विचार कर बनानी होगी। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

बीते वित्त वर्ष 2019–20 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 4.2 प्रतिशत रह गई है, जो इसका 11 साल का निचला स्तर है। बीते वित्त वर्ष की चौथी जनवरी–मार्च की तिमाही में वृद्धि दर 40 तिमाहियों के निचले स्तर 3.1 प्रतिशत पर आ गई है।

लॉकडाउन लंबा खिंचने से ये होगी दिक्कत

एसबीआई की शोध रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया है, अब हमारा मानना है कि हमें समझदारी के साथ लॉकडाउन से निकलने की रणनीति बनानी चाहिए। राष्ट्रव्यापी बंद लंबा खिंचने से वृद्धि दर में गिरावट भी लंबे समय तक रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व के अनुभवों से पता चलता है कि मंदी से बाहर निकलने की रफ्तार काफी धीमी रहती है। आर्थिक गतिविधियों के पुराने स्तर पर पहुंचने में पांच से दस साल लग जाते हैं।

कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा

जारी जीडीपी आंकड़ों पर रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च के अंतिम कुछ दिनों में बंद की वजह से चौथी तिमाही की वृद्धि दर 40 तिमाहियों के निचले स्तर 3.1 प्रतिशत पर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों की बात की जाए, तो सिर्फ कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा। बीते वित्त वर्ष में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर चार प्रतिशत रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2018–19 में 2.4 प्रतिशत रही थी।

जानवरों से मनुष्यों में कैसे पहुंचा कोरोना वायरस, रिसर्चर्स ने लगाया पता

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। कोविड–19 वैश्विक महामारी के स्रोत पर प्रकाश डालने वाले एक अध्ययन में बताया गया है कि कोरोना वारयस आकार बदलकर जानवरों से मनुष्यों में प्रवेश करने और उन्हें संक्रमित करने में सक्षम है। अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड–19 और जानवरों में इसके इसी प्रकार के प्रारूपों का आनुवंशिक विश्लेषण किया।

उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस वायरस का सबसे निकट संबंधी वही कोरोना वायरस है जो चमगादड़ों को संक्रमित करता है। अनुसंधानकर्ताओं के दल में अमेरिका के अल पासो में टेक्सास विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं।

उन्होंने साइंस एडवांसेस में प्रका. शित अध्ययन में कहा कि सार्स–कोव–2 वायरस की मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता स्तनधारी प्राणी पैंगोलिन को संक्रमित करने वाले कोरोना वायरस से एक अहम जीन के आदान–प्रदान से जुड़ी है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि यह वायरस अपने आनुवंशिक गुणों में बदलाव करके मेजबान कोशिकाओं में मौजूद रह सकता है। इसी क्षमता के कारण यह एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में प्रवेश कर सकता है।

उन्होंने कहा कि यह उसी प्रकार है, मानो वारयस में ऐसी क्षमता है कि वह चाबी को इस प्रकार ढालने में सक्षम है जो मेजबान कोशिका के द्वार को खोल सके।

अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के फेंग गाओ ने कहा कि सार्स या मर्स की तरह यह कोरोनावायरस भी अपने आनुवंशिक गुणों में बदलाव करने में सक्षम है जिसकी मदद से वह मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। गाओ और उनके साथियों के अनुसार इस अध्ययन से वायरस से भविष्य में होने वाली वैश्विक महामारियों को रो. कने और उनका टीका खोजने में मदद मिल सकती है।

कोरोना ने दिल्ली सचिवालय में भी दी दस्तक

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के कहर से कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उप–राज्यपाल कार्यालय के बाद कोरोना का यह संक्रमण अब दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया है। सचिवालय के एक कर्मचारी में ब्टप्क–19 वायरस की पुष्टि होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को सैनिटाइजेशन के लिए सील कर दिया। हालांकि, अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस से चार कदम आगे और हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या नहीं इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज कोई ये नहीं कह सकता कि एक महीना या दो महीने और लॉकडाउन कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा।

कोरोना रहेगा, अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस समय कोरोना के मरीजों का इलाज करने पर ध्यान दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ब्वअपक–19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 'आप' की सरकार कोरोना वायरस से चार कदम आगे है। हम इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम स्थायी लॉकडाउन नहीं कर सकते। कोरोना वायरस पर दिल्ली सरकार की तैयारियों की चर्चा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के कुल 17386 केस हैं। उसमें से 7846 लोग ठीक हो गए हैं और 9142 लोग अभी भी बीमार हैं। इनमें से 398 लोगों की मौत हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बीते 15 दिन में 8,500 मरीज बढ़े हैं, लेकिन अस्पतालों में सिर्फ 500 मरीज ही भर्ती हुए हैं। ज्यादातर लोगों को हल्के लक्षण हैं और वो घर पर होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हो रहे हैं। किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

कुल मरीजों में से केवल 2100 अस्पतालों में हैं, बाकी का उनके घरों में ही इलाज चल रहा है। कोरोना के इलाज के 6500 बिस्तर अब तक तैयार हैं और 9500 बिस्तर एक और हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को कोरोना से संबंधित किस अस्पताल में कितने बेड हैं इसकी सही जानकारियां मिलेंगी ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। इसके साथ ही केजरीवाल ने अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कृपया गंदी राजनीति न करें। फर्जी वीडियो या जानकारियां फैलाने से हमारे डॉक्टरों का मनोबल टूटता है और जनता में भ्रम पैदा होता। ऐसे समय में ये सब करना ठीक नहीं।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में भयावह रूप लेते जा रहे कोरोना वायरस ने अब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में भी दस्तक दे दी है। उपराज्यपाल कार्यालय के तीन और कर्मचारियों को कोविड–19 से संक्रमित पाया गया था। एक दिन पहले एक जूनियर सहायक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था।

अभी तक उपराज्यपाल सचिवालय में कोरोना वायरस संक्रमण के चार मामले सामने आ चुके हैं। सूत्र ने बताया कि दो जूनियर सहायकों और एक सफाई कर्मी को कोविड–19 से संक्रमित पाया गया।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD

- EVENTS MANAGEMENT
- PR MANAGEMENT
- ARTISTS MANAGEMENT

http://www.takshakindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Editorial

04

P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, मई, 2020

सम्पादकीय

भरोसे का टूटना

सत्येन्द्र सिंह

किसी भी लोकतांत्रिक देश में आम जनता जब किसी तरह के संकट में पड़ जाती है, तब उसकी उम्मीद यही होती है कि सत्ता और विपक्ष में बैठे उनके नेता परिस्थितियों को समझेंगे और मदद करेंगे। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बने मौजूदा हालात में देश भर में खासतौर पर गरीब मजदूरों के सामने जिस तरह का व्यापक संकट खड़ा हो गया है, उसमें लगभग सभी पार्टियों और नेताओं के रुख ने उनका भरोसा बहुत कमजोर कर दिया है। पूर्णबंदी की वजह से रोजी–रोटी या हर तरह के रोजगार सहित शहरों में रहने के ठिकाने तक से लाचार कर दिए गए मजदूरों के सामने लगभग सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। ऐसे में उनके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से बहुत देर से जो थोड़ी–बहुत व्यवस्था की भी गई, वह नाकाफी है। दूसरे राजनीतिक दलों या नेताओं ने भी बहुत गंभीरता या संवेदनशीलता नहीं दिखाई। दूसरी ओर, सड़क पर पैदल ही हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करते मजदूरों के साथ पुलिस का जो बर्ताव दिखा, उसने लोगों को भीतर से तोड़ दिया। यह बेवजह नहीं है कि अब बहुत सारे मजदूर इस भाषा में अपना दुख जाहिर करने लगे हैं कि हमने जिन नेताओं और पार्टियों पर भरोसा किया था, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। एक प्रवासी मजदूर का यह दुख सच से कितना अलग है कि चुनाव के वक्त नेता वादा करके, गरीबों के साथ सहानुभूति दिखा कर हमारे साथ खेलते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। ऐसे में अगर अभी मतदान की आयु में ही पहुंचा कोई युवक अगर भविष्य में किसी भी नेता या पार्टी को वोट नहीं देने की बात कहता है तो क्या उसकी तकलीफ को समझना मुश्किल है? जिस तरह गरीब प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए हादसों में, ट्रेन की पटरियों पर या भूख से दो–चार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, उसकी मूल वजह क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आज भी अगर किसी को इनकी परवाह नहीं है और नेताओं में एक तरह की बेरुखी कायम है तो इसे कैसे देखा जाएगा? स्वाभाविक ही परेशानहाल गरीबों और मजदूरों के भीतर मौजूदा हालत के खिलाफ दुख अब गुस्से के रूप में सामने आ रहा है। भरोसे का यह टूटना किसी तात्कालिक परिस्थिति का नतीजा नहीं है, बल्कि यह यह वह दुख है जो बहुत लंबे समय तक मजदूरों और गरीबों की तकलीफों की उपेक्षा के बाद जाहिर हो रहा है। महामारी से बचाव के लिए उठाए गए कदम निहायत जरूरी हैं। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता था कि देश भर में सब कुछ बंदी लागू करने के पहले लोगों को कुछ संभलने का मौका दिया जाता? इस बात का खयाल रखे बिना जो हुआ, उसका नतीजा दुनिया के सामने है। लाखों लोग जब मरते–जीते अपने गांवों की ओर लौटने लगे तो कुछ राज्य सरकारों का रुख भी आमतौर पर बेहद संवेदनहीन रहा। गांवों में सामाजिक वंचना और आर्थिक लाचारी के दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए मजदूरों ने इज्जत की दो रोटी के लिए शहरों का रुख किया था। अब वे वहीं वापसी के त्रासद हालात में झोंक दिए गए हैं। जनता के दुखों को दूर करने का वादा करके अपनी राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों को लेकर अब उनके भीतर रोष है, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अगर मजदूर सिर्फ इतनी–सी मांग कर रहे हैं कि हमें सहानुभूति नहीं, इज्जत चाहिए, तो क्या यह उनका अधिकार नहीं है?

लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट और मुनाफाखोरी के वाकये बढ़े

लॉकडाउन के दौरान बेईमान तत्व खाद्य पदार्थों में मिलवाट कर अनुचित लाभ उठा सकते हैं या स्थिति का फायदा उठाकर मिलावट और धोखेबाजी में लिप्त हो सकते हैं। मुनाफाखोरी पहले से ही तनावपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य और धन को गंभीरता से प्रभावित कर सकती है। सामान्यतरू बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय बना रहता है। दालें, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं है। आज मिलावट का सबसे अधिक कुप्रभाव हमारी रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली जरूरत की वस्तुओं पर ही पड़ रहा है। कोरोना के चलते वैसे भी इस समय हर किसी को मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है। शरीर के पोषण के लिए हमें खाद्य पदार्थों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु प्रोटीन, वसा, काबोर्हाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण आदि की पर्याप्त मात्रा को आहार में शामिल करना आवश्यक है तथा ये सभी पोषक तत्व संतुलित आहार से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यह तभी संभव है, जब बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री, दालें, अनाज, दुग्ध उत्पाद, मसाले, तेल इत्यादि मिलावट रहित हों। खाद्य अपमिश्रण से उत्पाद की गुणवत्ता काफी कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों में सस्ते रंजक इत्यादि की मिलावट करने से उत्पाद तो आकर्षक दिखने लगता है, परंतु पोषकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए या उसमें से कोई मूल्यवान पोषक तत्व निकाल लिया जाए या भोज्य पदार्थ को अनुचित ढंग से संग्रहित किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए उस खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थ को मिलावटयुक्त कहा जाएगा। भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की मिलावट की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन् 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (पीएफए एक्ट 1954) लागू किया गया। उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस समय मूल खाद्य पदार्थ तथा मिलावटी खाद्य पदार्थ में भेद करना काफी मुश्किल है। अपमिश्रित आहार का उपयोग करने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकार उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। खाद्य अपमिश्रण से जहां कोरोना के दौरे में रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी वहीं अन्य बीमारियां भी जैसे आंखों की रोशनी जाना, हृदय संबन्धित रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र के रोग, पक्षाघात व कैंसर जैसे रोग भी ज्यादा प्रभवि हो सकते हैं। इस समय लोग ज्यादातर घरों और चूल्हों तक सीमित हैं। वो ज्यादा समय नहीं दे सकते और न ही इस दौरान पता कर सकते की बाजार में क्या है, जो जैसे भी मिल पा रहा है जल्दबाजी में खरीद रहे है, समय भी ऐसा ही है और न ही उनके पास ऐसे समय खरीददारी के विकल्प बचे हैं। यह काफी प्रेरणादायक है कि इस तरह के समय के दौरान खाद्य खाद्य और औषधि प्रशासन की सुरक्षा विंग विभाग ने निरीक्षण की आवश्यक पहल की है। अच्छा व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठान उत्पादित किए जा रहे खाने की गुणवत्ता की प्रथाओं और रखरखाव को ताक पर रखकर आज कार्य कर रहे हैं। सरकार को ऐसे समय ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस समय कोई भी अनुचित लाभ न उठा सके। तालाबंदी के कारण लोगों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी संदेह हो रहा है। बाजार में बेचे जा रहे खाने के सामानों की गलत और भ्रामक जानक. ारी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाढ़ आ गई है। ये ज्यादा चौंकाने वाला और डरावना है, प्रशासन को इस पर कठोर करवाई कर लगाम लगानी होगी। कई जगह घटनायें सच भी हैं जहां खाद्य पदार्थ जो सब स्टैंडर्ड थे बिना किसी कानून का संकोच या डर के बाजार में बेच दिए गए। हालांकि वहां वांछनीय कार्रवाई की गई और खराब गुणवत्ता वाले खाने को या तो जब्त कर लिया गया या नष्ट कर दिया, लेकिन विचार करने के लिए बिंदु यह है यह सब कैसे हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की दुर्भावना में लिप्त हैं और वो लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। वक्त की जरूरत है कि उक्त विभाग खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करें और जो कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल है उनके खिलाफ सख्त करवाई तुरंत अमल में लायें। मिलावटी पदार्थों से बचने और अपमिश्रण की पहचान के लिए प्रशासन के साथ–साथ हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। खाद्य अपमिश्रण एक अपराध है। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत किसी भी व्यापारी या विक्रेता को दोषी पाये जाने पर कम से कम 6 महीने का कारावास, जो कि तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मानदण्ड का भी प्रावधान है। खाद्य पदार्थों में मानव स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और इसकी रोकथाम में उपभोक्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उपभोक्ता (विशेषकर गृहिणियों) को अपमिश्रण से बचने हेतु जागरूक होना चाहिए। इसके लिए कुछ आवश्यक बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए जैसे खुली खाद्य सामग्री न खरीदें। अधिकतर मानक प्रमाण चिन्ह (एगमार्क, एफपीओ, आईएसआई, हॉलमार्क) अंकित सामग्री खरीदें तथा खरीदे जाने वाली सामग्री के गुणों, रंग, शुद्धता आदि की समुचित जानकारी रखें। दुकानदारों व सत्यापित कम्पनियों का सामान लें तथा जहां तक हो सके पैकेज्ड सामान का उपयोग करते समय कम्पनी का नाम व पता, खाद्य पैकिंग व समाप्ति की तिथि, सामान का वजन, गुणवत्ता लेबल का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि स्वस्थ और निरोगी जीवन ही सफलता की कुंजी है। कोरा. ना काल में वैसे भी हमें और ज्यादा जागरूक बनने की जरूरत है।

कोरोना से बचना है तो जरूर पिएं हल्दी वाला दूध या पानी

कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आए दिन वैज्ञानिक कुछ न कुछ नई खोज कर रहे हैं। ऐसे में लोग अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए कई उपाय कर रहें हैं। और जैसा की आप सभी जानते हैं कि हल्दी गुणों की खान है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी इम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं और सर्दी खांसी को भगा सकते हैं। हल्दी बेहद गुणकारी होती है। हल्दी एक ऐसी जड़ी–बूटी है जिससे शरीर को अत्यधिक लाभ मिलते हैं। आमतौर पर अंदरूनी चोट लगने पर या हाथ–पैरों में दर्द से राहत पाने के लिए हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हल्दी को सिर्फ दूध में या खाने में ही नहीं बल्कि गर्म पानी में भी मिलाकर पीने से स्वस्थ रहा जा सकता है।

हल्दी और गर्म पानी के फायदे

हल्दी में प्रचुर मात्रा में एंटीसेप्टिक व एंटीबॉयटिक पाया जाता है। जिसका सेवन करने से सूजन–रोधी और रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ती है। चिकित्सकों के अनुसार हल्दी में लिपोपोलीसैचिरिड नामक तत्व होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। हल्दी के बैक्टीरिया रोधी प्रभाव से शरीर में हुए घाव को जल्दी भरने में मदद मिलती है। जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से बचाव करने में हल्दी का पानी अधिक लाभकारी है। साथ ही हल्दी

खून को गाढ़ा होने से भी बचाती है जिससे हार्ट–अटैक की संभावना कम हो जाती है। हार्ट की समस्या से परेशान लोगों को हल्दी वाले पानी का सेवन करना चाहिए। हल्दीयुक्त पानी आंखों की बीमारियों में भी गुणकारी है। इस पानी में दुखती या सूजी हुई आंखें धोने से काफी फायदा होता है। बीमारी से जुड़ी रीसर्च में सामने आया है कि हल्दी के पानी के सेवन से कैंसर जैसी बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है क्योंकि इसम ट्यूमर को रो. कने के गुण होते हैं। हल्दी हमारे अंदर मौजूद बैड कोलेस्ध्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में मदद करता है। हल्दी के पानी के सेवन करने से मोटापे की समस्या दूर होती है। यह शरीर में फैट बढ़ाने वाले टिश्यू को बनने से रोकता है। इतना ही नहीं, त्वचा संबंधी कई समस्याओं में हल्दी का सेवन काफी फायदेमंद है। यह आपकी स्किन में निखार लाने का काम करता है।

हल्दी का पानी कैसे बनाएं : गैस पर एक गिलास पानी उबलने के लिए रख दें। अब इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पॉउडर डाल कर अच्छी तरह मिला लें। आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। हर दिन इसी तरह हल्दी के पानी का सेवन करें।

कब पिएं हल्दी का पानी : हल्दी के पानी का सेवन रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए। सुबह के समय इस पानी को पीने से आपको ज्यादा फायदा होगा। हल्दी को हम तुलसी के पत्ते के साथ भी ले सकते हैं। तुलसी के पत्ते की बात करें तो तुलसी भी हर किसी के घर मे बड़ी आसानी से मिल जाती है। तुलसी भी सर्दी, खांसी, जुखाम व फ्लू जैसी बीमारियों से हमें बचाती है। साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम भी करती है। रोज सुबह तुलसी के 5–6 पत्ते तोड़कर उसे चबाना चाहिए। अगर किसी के घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार में तुलसी अर्क मौजूद है। उसकी पानी मे कुछ बूंदे डाल कर रोज सेवन करें। यह काफी लाभकारी होगा।

बार्डर पर जाम बरकरार, बैगर पास वालों को एंट्री नहीं दे रही पुलिस

–उद्योग विहार (मई 2020)–

गाजियाबाद। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार संख्या बढ़ने के बाद दिल्ली से सटे यूपी बॉर्डर, यूपी गेट, महाराजपुर–आनंद विहार और नोएडा के बॉर्डर सील किए जाने की वजह से तीसरे दिन फिर बॉर्डर क्षेत्रो में वाहनों का भीषण जाम लग गया। बगैर पास वाले वाहनों की जहां पुलिस ने एंट्री नहीं होने दी। वहीं, बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सीमाओं को सील कर रखा। जिसके चलतें सड़कों पर भारी जाम लगने की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दियें। दरअसल दिल्ली भी इन दिनों कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं,गाजियाबाद में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढने की वजह से जिलाधिकारी डॉ.अजय शंकर पांडेय ने फिर दोबारा से सोमवार को दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया था। लॉकडाउन–2 की तरह लॉकडाउन–4 में फिर से दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया हैं। जिलाधिकारी द्वारा सीमा सील करने के आदेश देने के बाद से केवल पास वालों को गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी गई हैं। उसी क्रम में

लोनी के एसडीएम खालिद अंजुम खान, बॉर्डर पर इंदिरापुरम सीओ अंशु जैन, कौशांबी थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह के अलावा सीओ साहिबा. बाद राकेश मिश्रा अपने–अपने क्षेत्रों में पुलिस फोर्स के साथ बॉर्डर पर निगाहबानी रखते हुए वाहनों की चेकिंग करने के बाद पास वाले वाहनों की एंट्री होने दी। आदेश के तहत सुबह नौ बजे से ही एंट्री बंद कर दी गयी। तीसरे दिन बुधवार क ी सुबह से ही बॉर्डर पर वाहनों का जाम लग गया। डीएम की ओर से नौ स्थानों पर तैनात किये गये मजिस्टेªटों के भी पसीनें छूट गये। लॉकडाउन की अवधि में लगातार तीसरे दिन भी जाम ने चिलचिलाती गर्मी में लोगो को रूला दिया। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारी भी जाम में फंस गए। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर लॉकडाउन–टू की तरह ही सील किए गए हैं। इन क्षेत्रों से केवल उन्हीं लोगो का आवागमन हो सका, जिनके पास प्रशासनिक पास रहा। डॉक्टरो और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, मीडिया कर्मी, बैंक कर्मियों और केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को सिर्फ आईडी कार्ड दिखाने पर ही छूट दी गई।

कूडे से भी संक्रमण फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है : राजेंद्र त्यागी

–उद्योग विहार (मई 2020)–

गाजियाबाद। बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कोरोना से प्रभावित शहर के हाट स्पाट एरिया से निकलने वाले कूडे को सैनिटाइज करने और निगम स्टाफ को मास्क, दस्ताने और साबुन दिए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हाट स्पाट एरिया से निकलने वाले कूडे से भी संक्रमण फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

वजह हाट स्पाट एरिया में घर–घर कूडा कलेक्शन के लिए जाने वाली गाडियों में कोरोना से प्रभावित व्यक्ति के द्वारा डाला गया कूडा भी हो सकता है। वैसे भी जानकारी में लाया गया कि देश के दूसरे हिस्सों में भी कूडे को सैनिटाइज करने पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम तो ये है कि निगम के जितने भी कर्मी है, उन्हें मास्क, दस्ताने और साबुन उपलब्ध कराया जाए, ताकि साबुन से निगम के कर्मी अच्छी तरह से हाथ साफ कर सकें।

श्री त्यागी ने कहा कि ये भी जानक. ारी में आया कि शहर के दूसरे वार्डो में कूडा कलेक्शन के लिए जाने वाली गाडियों में लोग जब कूडा डालने के लिए आते है, वह मास्क नहीं लगाए होते है। लोगों के लिए आवश्यक है कि जब घर से बाहर कूडा डालने आए तो वह मास्क के साथ हाथों में दस्तानों का अवश्य इस्तेमाल करें।

उन्होंने कहा कि ये भी देखने में आ रहा है कि कालोनियों में सब्जी बेचने आने वाले लोग मास्क आदि नहीं पहने होते है। इसके साथ–साथ सब्जी खरी. दने के लिए आने वाली महिलाएं और पुरूष भी मास्क और दस्ताने नहीं पहने होते है। ये बडा ही गंभीर विषय है। दुनिया में महामारी का रूप धारण किए कोरोना को ध्यान में रखते हुए सावधानी सबसे अहम है। जैसा कि देश के कई प्रांतों खासकर गुजरात के अहमदाबाद आदि में सब्जी आदि खरी. दने के दौरान एहतियात न बरते जाने के चलते कोरोना के मामले बढने की बातें सामने आ रही है।

शहीदों को दी श्रद्धांजलि

–उद्योग विहार (मई 2020)–

हापुड़। सन 1857 10 मई को मेरठ से शुरू हुई जंगे आजादी की लड़ाई में शहीद हुए क्रांतिवीरों को लोगों ने याद किया। शहीद स्तंभ व शहीद तात्या टोपे की प्रतिमा पर माल्यपर्ण कर दीप, मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रामलीला मैदान पर स्थित शहीद तात्या टोपे व शहीद स्तंभ पर लोग पहुंचकर शहीदों को नमन कर रहे है। दिन में काफी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सायं दीप जलाएं गए। स्वाधीनता संग्राम शहीद स्मारक समिति के पदाधिकारियों ने शहीद स्तंभ तथा शहीद तात्य टोपे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान समिति के चेयरमैन ललित अग्रवाल छावनी वालों ने कहा कि शहीद के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वैसे तो समिति शहीदों की याद में एक माह का शहीद मेला लगाती है। लेकिन इस बार कोरोना संकट व लॉकडाउन के तहत मेला नहीं लगेगा। वहीं महामंत्री मुकल त्यागी ने बताया कि उनका गांव असौड़ा हॉटस्पॉट है। सील होने के कारण वह शहीद स्तंभ पर नहीं जा सकें। उन्होंने घर पर ही शहीदों की याद में दीए जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सपा नेता पुरुषोत्तम वर्मा, कांग्रेस नेता ललित शर्मा, रालोद नेता नानकचंद शर्मा, अनिल आजाद एडवोकेट ने शहीद स्तंभ पर जाकर शहीदों को याद किया। वहीं गांव वझीलपुर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी ने भी अपने आवास पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीदों की कुर्बानी को कभी नहीं भुला सकेंगे। शहीदों के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले रहे है।

प्रशासन ने विदेश से लौटे 35 लोगों को ठहरने की व्यवस्था कर उन्हें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई हैं

–उद्योग विहार (मई 2020)–

गाजियाबाद। जहाँ जिला प्रशासन ने विदेश में फँसे बंगलादेश से हवाई यात्रा से लौटे 35 लोगों को ठहरने की व्यवस्था कर उन्हें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई हैं, वहीं प्रदेश सरकार के निर्देश पर दूसरे राज्यों से आने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों को छोड़ने के लिए भी कार्य जारी रहा, और प्रशासन ने 3000 मजदूरों को उनके गृह जनपद तक 80 बसों से रवाना किया। इतना ही नहीं देर रात तक मजदूरों को छोड़ने का कार्य चलता रहा। खास बात यह रही कि प्रत्येक बस में एक श्रमिक को टीम कमांडर बनाया तो वहीं बंगलादेसियों के लियें ग्रुप केयर टेकर बनाकर उन्हें कोई भी समस्या होने पर अवगत कराने के लियें जिलें के अधिकारियों के फोन नंबर की सूची सौंपी। बंगलादेश से लौट 35भारतीयों के साथ ही प्रवासी तीन हजार मजदूरों की पहलें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग की और उसके बाद हवाईयात्रा करने वालें यात्रियों को 14 दिन के लियें क्वाटराईन सेंटर में भेजा गया। उनका ग्रुप केयर टेकर बनाकर एक को जिम्मेदारी सौंपी गयी कि किसी को भी भोजन से लेकर स्वास्थ्य की परेशानी हो तो वह जिलामुख्यालय के कंट्रोल रूम के फोन न0–0120ध्2821616 पर फ ोन क र समस्या का निराकरण करा सकता हैं। वही दूसरी ओर प्रवासी श्रमिको को विभिन्न खुलें स्थानों पर रोककर उनको बस में बैठाया गया। सभी तीन हजार मजदूरों को खाना खिलाया गया, ताकि कोई भी मजदूर भूख के कारण परेशान न हो। वहीं आंधी व बारिश के कारण मजदूरों को छोड़ने के कार्य में काफी बाधा आयी। स्वयं डीएम अजयशंकर पांडे व एसएसपी कलानीधि नैथानी ने पहुंचकर मजदूरों से सीधा संवाद किया। कामगारों को भेजने के लिए स्क्रीनिग कैम्प बनाया गया था। हरियाणा से अमेठी, बलिया, सुल्तानपुर, आजम गढ़, मऊ, भदोही, चन्दौली, कासगंज, सोनभद्र, अम्बेडकर नगर, बदायूं, एटा आदि में स्थानों पर कामगारों को बसों से उनके गन्तव्य की तरफ रवाना कर दिया गया था। इस मौके पर डीएम व एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसडीएम सदर आदित्य प्रजापति, अपर नगर मजिस्ट्रेट डीपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट शिवप्रकाश शुक्ल, एसपी सिटी मनीष मिश्रा, एसी देहात नीरज जादौन सहित अन्य अधिकारियों के साथ हाईवे व ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे का भी निरीक्षण किया और मजदूरों के बारे में जानकारी ली। जिन्हें खाना आदि खिलाकर उनके गन्तव्य की तरफ रवाना कर दिया गया।

बिना रजिस्ट्रेशन के आए कामगार बने फुटबॉल

दूसरे राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही पैदल आने वाले यात्री फुटबॉल बनकर रह गए है। रविवार को सैकड़ो कामगारों को प्राइवेट वाहन से यूपी बार्डर से लेकर अन्य जनपद की सीमाओं पर चालक उतारकर फरार हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ठहरावस्थल पर पहुंचा दिया, लेकिन शाम तक उन्हें ना भेजे जाने पर ग्रामीणों ने उनके रुकने का विरोध शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वाहनों में बैठाकर बागपत रवाना किया। लेकिन बागपत पुलिस ने फिर से उन्हें गजियाबाद में ही ला छोड़ा। इस तरह से कामगार रात भर सड़को पर फुटबॉल की तरह इधर से उधर भटकते रहे। उन्होंने प्रशासन से उनके गन्तव्य तक पहुंचाने की गुहार लगाई है।

सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सहित अन्य मानक करने होंगे पूरे

गाजियाबाद। कोरोना के चलते लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने से पहले जिला प्रशासन ने महानगर में छोटे–बड़े निर्माण कार्य को अब छूट दे दी है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अब सरकारी एजेंसियों, बिल्डरों और ठेकेदारों को जीडीए से मंजूरी नहीं लेनी होगी। अब विभागीय स्तर पर ही निर्माण की मंजूरी दी जाएगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया के साथ निर्माण साइटों पर केंद्र सरकार के मानकों को पूरा कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती होगा। जीडीए की ओर से बीते मंगलवार तक 146 निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब जनपद में कहीं भी छोटे–बड़े निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए अब मंजूरी नहीं लेनी होगी। ऐसे में गली मोहल्लों में शुरू होने वाले निर्माण कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल करना बेहद कठिन होगा। जिला प्रशासन की ओर से निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तय किए गए मानकों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ऐसे में विभिन्न निर्माण एजेंसियों के ऊपर ही मानकों को पूरा कराने का दारोमदार होगा। जीडीए सहित अन्य ने निर्माण एजेंसियों को सबसे ज्यादा परेशानी निजी ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की निगरानी में पेश आ सकती है। पूर्व की तरह ही निर्माण करने वालों को अपनी साइट पर श्रमिकों का नियमित मेडिकल चेकअप कराने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य है। साथ ही निर्माण स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग, साइट पर सैनिटाइजेशन के साथ प्रवेश द्वार पर हैंडवाश, पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य है। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि प्राधिकरण के प्रोजेक्ट के साथ जीडीए क्षेत्र में आने वाले निर्माण कार्यों पर मानक. ों का पालन हो रहा है या नहीं।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

उद्योग–जगत

06 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, मई, 2020

15 वें वित्त आयोग द्वारा गठित समिति सरकार की राजकोषीय स्थिति की मजबूती को लेकर करेगी बैठक

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से गुरुवार को पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत गठित एक समिति विचार विमर्श करेगी। इस समिति की अध्यक्षता एन के सिंह कर रहे हैं। इस समिति को वित्त वर्ष 2021–22 से लेकर वित्त वर्ष 2025–26 तक के समय के लिए केंद्र व राज्यों की राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने की कार्ययोजना तैयार करने का जिम्मा मिला है। इस बारे में एक अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नई आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा कर मजबूत राजकोषीय स्थिति की कार्ययोजना के लिए गठित समिति गुरुवार को एक ऑनलाइन बैठक करेगी।

विज्ञप्ति के अनुसार, कोरोना वायरस प्रकोप के चलते अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिस्थितियां पैदा हुई हैं और इसके चलते केंद्र व राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करना

काफी पेचीदा काम हो गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा दिया है। केंद्र ने इसे बढ़ाकर राज्यों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पांच फीसद कर दिया है। पहले यह सीमा जीएसडीपी की तीन फीसद थी।

विज्ञप्ति के अनुसार, एन के सिंह की अध्यक्षता वाली समिति कर्ज और घाटे को उचित स्तर पर रखते हुए उच्च समावेशी वृद्धि के साथ केंद्र व राज्यों की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने वाली कार्ययोजना के लिए अपनी सिफारिशें सौंपेगी। इस कार्य में समिति पारदर्शिता रखते हुए न्यायसंगत रहेगी। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा बीती 18 मार्च को केंद्र व राज्य सरकारों की राजक. ोषीय स्थिति को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष एन के सिंह के साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार कृ ष्णमूर्ती सुब्रमण्यम, पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य अनूप सिंह और अजय झा, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रजत कुमार, महालेखा नियंत्रक सोमा राय बर्मन, पंजाब सरकार के प्रधान सचिव अनिरुद्ध तिवारी और तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस कृष्णन के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा 15 वें वित्त आयोग ने कोविड–19 महामारी के संदर्भ में संसाधनों और कार्यबल को बढ़ाने की जरूरत पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय समूह के साथ एक बैठक भी आयोजित की है। इस उच्च स्तरीय समूह में डॉ. गुलेरिया, नारायणा हेल्थ सिटी के अध्यक्ष डॉ देवी शेट्टी, और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान के वाइस चांसलर डॉ. दीलिप गोविंद भी शामिल हैं।

गिर गई सोने की वायदा कीमतें, चांदी में भी भारी गिरावट

नई दिल्ली। वायदा बाजार में सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स एक्सचेंज पर पांच जून 2020 के सोने की वायदा कीमत 256 रुपये की गिरावट के साथ 46,875 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। वहीं, गुरुवार सुबह एमसीएक्स पर पांच अगस्त 2020 के सोने का वायदा भाव 0.31 फीसद या 149 रुपये की गिरावट के साथ 47,191 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। सोने की वैश्विक हाजिर और वायदा कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में गुरुवार को भारी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर तीन जुलाई 2020 की चांदी की वायदा कीमत 1.43 फीसद या 703 रुपये की गिरावट के साथ 48,355 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो यहां सोने का वायदा और हाजिर भाव गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहा था। ब्लूमबर्ग के अनुसार, कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 0.50 फीसद या 8.80 डॉलर की गिरावट के साथ 1743.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था।

आर्थिक पैकेज के साथ सुधारों की फेहरिस्त, एक तीर से दो निशाने

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। कोरोना पैकेज के वक्त सुधारों की लंबी फेहरिस्त देखकर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इसी वक्त क्यूं? आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद एक बात है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। अपने पहले कार्यकाल में जीएसटी पर भारी विरोध झेल चुके प्रधानमंत्री के लिए चुनौती का काल अवसर भी लेकर आया। जितने भी सुधार किए गए हैं उसके प्रयास लंबे अरसे से होते रहे हैं, लेकिन विवादों के मकड़जाल में ऐसा घिरा कि कभी जमीन पर नहीं उतर पाया। आगे बढ़ने की चाह और होड़ में यह तय माना जा रहा है कि फिलहाल तो राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध नहीं होगा। वहीं राज्यों में भी सुधार की शुरुआत होगी। दरअसल, ये सुधार ही आत्मनिर्भर भारत की नींव होंगे।

आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955

इस कानून के पुराने पड़ चुके प्रावधानों को हटाने को लेकर पिछली सरकारों ने कभी प्रयास नहीं किया। खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर होने के साथ अब निर्यात भी करने लगा है। फिर भी इसकी प्रतिबंधित जिंसों की सूची में चावल, गेहूं, दलहन और तिलहन के साथ आलू व प्याज बनी हुई है। इसके चलते इन जिंसों में खाद्य प्रोसेसिंग सेक्टर, निर्यातकों और बड़े उपभोक्ताओं को जहां मुश्किलें पेश आती थीं, जिसका सीधा असर किसानों के हितों पर पड़ता है। सरकार ने इन जिंसों को बाहर करने का फैसला करके बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है।

एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट

एपीएमसी या मंडी एक्ट के नाम से भी मशहूर यह प्रावधान किसानों के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है। इसमें संशोधन अथवा इसे हटाने को लेकर राज्यों का हित आड़े आता रहा है। आर्थिक हितों के साथ राजनीतिक वजहें भी प्रमुख हैं। स्थानीय कमेटियों के गठन में राजनीतिक दलों के हित प्रभावित होते हैं। कृषि उपज के कारोबार में बिचौलियों का एकाधिकार बना हुआ है। वर्ष 1999 में पहली बार तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें संशोधन के लिए मॉडल एपीएमपी एक्ट बनाकर राज्यों को भेजा, लेकिन

राज्यों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। मौजूदा सरकार ने भी वर्ष 2017 में इसे पुनः संशोधित कर एक मॉडल एक्ट राज्यों को भेजा है, जिसमें राज्यों की ओर से कोई खास रुचि नहीं दिखाई गई। लिहाजा सरकार को अब केंद्रीय एपीएमसी एक्ट बनाने की घोषणा करनी पड़ी है।

कृषि मूल्य उपज और गुणवत्ता आश्वासन

कृषि सुधार के लिए इस तरह के कानून की अवधारणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान की गई थी। लेकिन लागू करने का दायित्व राज्यों पर होने की वजह से यह अभी तक लागू नहीं हो सका है। इसमें कांट्रैक्ट फार्मिंग सबसे अहम प्रावधान है। इसके लागू हो जाने के बाद उन किसानों को फायदा होगा, जो मांग आधारिक खेती पूर्व निर्धारित मूल्य पर करना चाहते हैं। इससे खेती में जोखिम कम हो जाएगा।

कोयला खदानों के इस्तेमाल की छूट

कोयला खदानों का आवंटन भारतीय राजनीति में एक संवेदनशील मामला है। इस चक्कर में यूपीए–दो को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। एक तरफ देश में कोयले का भरपूर भंडार दूसरी तरफ इसका बढ़ता आयात। निजी कंपनियों को इसका इस्तेमाल करने में पूरी आजादी देने का दो टूक फैसला लेने में तमाम अड़चनें। कोविड–19 ने जो हालात बनाये उसने इन अड़चनों को दूर कर दिया। अब कोयला खदानों को कमर्शियल माइ. निंग के लिए देने का फैसला हो चुका है, यानी जो कंपनी खदान लेगी उसे इसका इस्तेमाल करने की पूरी छूट होगी। कोयला उत्पादन बढ़ेगा, आयात कम होने से विदेशी मुद्रा बचेगी।

टैरिफ पॉलिसी को मंजूरी

चुनावी मौसम में बिजली पर राजनीति कोई नई बात नहीं। अब जबकि कई राज्यों के चुनाव में मुफ्त बिजली एक बड़ा नारा बन कर उभरी है, तब मोदी सरकार ने कोविड–19 के काल में जो सुधार किये हैं उसमें इससे जुड़ा फैसला भी है। इसका बिजली उद्योग के साथ ही श्रमिक संगठनों व राजनीतिक दलों की तरफ से भी विरोध हो रहा था। नई टैरिफ पॉलिसी चौबीसों घंटे बिजली देगी लेकिन यह बिजली पर राजनीति को हमेशा के लिए रोक देगी।

श्रम सुधारों को आगे बढ़ाया

जब से देश में आर्थिक सुधार लागू हुए हैं तभी से श्रम सुधार हर सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। कई समितियों और कई बार कैबिनेट नोट तैयार करने के बावजूद इस पर फैसला नहीं हो सका। मोदी सरकार ने भी पहले कार्यकाल में दम दिखाया लेकिन जमीन तौर पर फैसला अब हो पाया है। जो संकेत दिए गए हैं उसके मुताबिक मौजूदा श्रम कानून का मिजाज पूरी तरह से बदला होगा।

बेड़ियों से मुक्त कृषि और किसान

किसानों को लेकर गंभीर प्रयास भी हुए हैं और इतिहास में राजनीतिक ताने–बाने का आधार भी किसान रहा है। लेकिन एक बार कृषि सुधारों की राह तैयार हो गई तो यह कहा जा सकता है अब से पहले किसान कभी इतने मुक्त नहीं रहे। मनरेगा के तहत कुल एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें बजटीय प्रावधान 61 हजार करोड़ के अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। जल संसाधन को मनरेगा की कार्यसूची में शामिल किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए आठ सूत्रीय घोषणा की गई है, जिसमें कृषि क्षेत्र के ढांचागत विकास, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी–बूटी व मधुमक्खी पालन और आपरेशन ग्रीन जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है।

आजादी के बाद पहली बार स्वास्थ्य प्राथमिकता में

सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य भी शुमार है। पिछले साल सरकार ने जीडीपी का 1.5 फीसद स्वास्थ्य पर खर्च किया था, जिसे इस साल बढ़ाकर 1.6 फीसद किया गया। सरकार का लक्ष्य इसे 2025 तक 2.5 फीसद तक ले जाने का था। माना जा रहा है कि इस लक्ष्य को 2023 तक पूरा करने की कोशिश होगी।

रक्षा उत्पादन को मिलेगा नया आयाम

चीन के मुकाबले भारत को विदेशी निवेश का बड़ा बाजार बनाने की कवायद सिरे चढ़ने लगी है। कुछ राज्यों में जहां श्रम सुधार की शुरूआत हुई है वहीं रक्षा में 74 फीसद विदेशी निवेश ने दुनिया की बड़ी–बड़ी रक्षा कंपनियों के लिए भारत को आकर्षक बना दिया है। भविष्य में राफेल से लेकर सुखोई जैसे लड़ाकू जेट भी बनने का रास्ता खुल गया है। भारत का रक्षा आयात घटेगा जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। रक्षा और सैन्य जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

राष्ट्रीय

07 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, मई, 2020

हमले के दौरान 100 गुना प्रजनन करती हैं टिड्डियां, जहां रुकें वहां जरूर देती हैं अंडे

—उद्योग विहार (मई 2020)—

नई दिल्ली। प्रवासी कीट यानी टिड्डी दल पाकिस्तान होते हुए भारत के कई राज्यों में प्रवेश कर चुका है। हालांकि सरकार की ओर से इसे रोकने और मारने के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के रिटायर विभागाध्यक्ष और जूलॉजी में कीट विज्ञान शाखा के अध्यक्ष रह चुके प्रो. राजेंद्र सिंह बताते हैं कि टिड्डियां हमला करने के दौरान बेहद आक्रामक हो जाती हैं। इनके शरीर का रंग व आकार बदल जाता है। हमले के दौरान टिड्डियों के प्रजनन की क्षमता 100 गुना तक बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि टिड्डियों के हमले मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में होते हैं।

यही वजह है अफ्रीका से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जरिए भारत में प्रवेश कर रही हैं। वह गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत शुष्क प्रदेशों में खेतों की खड़ी फसल को चट कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर यह एक स्थान पर रहती हैं। कभी–कभी यह तेजी से हमला करती हैं। इस दौरान उनके शरीर की संरचना बदल जाती है।

हरे–पीले रंग की टिड्डियों के शरीर का रंग बदल कर हल्का भूरा व गुलाबी हो जाता है। माइग्रेशन के दौरान पिछले पैरों की हड्डियों का आकार भी बदल जाता हैं। इतना ही नहीं, इनकी प्रजनन की क्षमता माइग्रेशन के दौरान 100 गुना तक बढ़ सकती है। ये जहां भी रुकती हैं, वहां अंडे जरूर देती हैं। इन अंडे को वे गड्ढों में दबा देती हैं। जहां से 15 से 20 दिन बाद अंडे फूटने लगते हैं।

करती हैं लंबा सफर : टिड्डियों का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसरका ग्रिगेरिया है। टिड्डियों का दल रोजाना 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इनके दल का आकार भी तीन से पांच किलोमीटर का होता है। अपने माइग्रेशन के दौरान हर झुंड में करोड़ों टिड्डियां मौजूद रहती हैं। ये एक साथ एक जगह से दूसरे जगह पर जाती हैं और खेतों में खड़ी फसल को चट कर जाती हैं।

हिमालय तराई व नम क्षेत्र से रहती हैं दूर : हिमालय के तराई क्षेत्रों में टिड्डियों के हमले का खतरा अपेक्षाकृत कम है। यहां हवा में नमी होती हैं। यहां अक्सर बारिश हो जाती है। यह मौसम का परिवर्तन टिड्डियों को नहीं भाता है। हवा में नमी होने व बारिश से टिड्डियों की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। यहीं वजह है कि पूर्वांचल में टिड्डियों के हमले का खतरा कम है।

सरकार ने ऑफिस आने-जाने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप किया अनिवार्य

—उद्योग विहार (मई 2020)—

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 के दौरान प्रतिबंधों में और अधिक ढील दे दी है। इस नए चरण को 30 जून तक विस्तारित किया जाएगा। सरकार कोरोना वायरस के संपर्क का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी कार्यालय जाने वालों के आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। ऐसा न करने वालों पर लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। सरकार ने जारी एक बयान में कहा, आरोग्य सेतु मोबा. इल ऐप्लिकेशन कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की त्वरित पहचान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी

प्रसाशनिक अधिकारी, लोगों को इस मोबाइल एप्लिकेशन को उपयोग करने की सलाह दें। केंद्र ने कहा कि कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के मोबा. इल में संपर्क ट्रेसिंग ऐप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। केंद्र ने सभी जिला प्रशासन से कहा कि वह व्यक्तियों को न केवल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दें, बल्कि नियमित रूप से इस पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति भी अपडेट करें। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा, सभी धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं और यहां तक कि शॉपिंग मॉलों को 8 जून से नॉन–कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति देकर नॉन–कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए राहत दी है। नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी कम कर दिया गया है। हालांकि, केंद्र ने चेतावनी दी है कि शेष प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उल्लंघन करने वालों को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। केंद्र ने चेतावनी में कहा, अगर कोई इन उपायों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने शनिवार शाम को 30 जून तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। लॉकडाउन का चौथा चरण रविवार आधी रात को समाप्त होगा।

जुलाई में स्कूल–कॉलेज खोलने पर विचार, उसके बाद शुरू हो सकती है मेट्रो

नई दिल्ली। लॉकडाउन से लोगों को राहत देते हुए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी गतिविधियों को एक जून से शुरू करने की इजाजत दी गई है। हालांकि, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक स्थलों समेत कई अन्य चीजों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। लेकिन, अन्य चीजों को चरणबद्ध तरीके से सरकार शुरू करेगी। केन्द्र सरकार ने कहा कि जुलाई में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "स्कूल, कॉलेजों, शिक्षा, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों जैसी चीजों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सलाह मशविरे के बाद खोला जाएगा। राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रशासन संस्थान के स्तर पर पैरेंट्स और अन्य लोगों से बात कर सलाह मिशविरा कर सकते हैं। उस फीडबैक के आधार पर जुलाई के महीने में इन संस्थानों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा।" कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अन्य मंत्रालयों और सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए डिपार्टमेंट हेड के साथ सलाह लेने के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) की एक लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में स्कूल–कॉलेजों को खोलने के बाद मेट्रो को खोलने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के बाद अगले नोटिस तक आम लोगों के लिए मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि फेज दो के दौरान जुलाई में स्कूल–कॉलेज पर फैसले के बाद मेट्रो को फेज–3 में चलने की अनुमति दी जा सकती है। गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय विमानों की अगस्त से पहले शुरू किया जा सकता है। ऐसे में गृह मंत्रालय ताजा गाइडलाइन्स के बाद यह संभव है कि अगस्त में अंतरराष्ट्रीय विमानें और मेट्रो सेवाएं चालू की जाएं। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की इजाजत दी जाती है। लेकिन, कुछ चीजें जैसे मॉल्स और रेस्टोरेंट को फेज के अनुसार शुरू किया जाएगा और कुछ चीजों पर अभी फैसला नहीं किया गया है।

चार में से एक भारतीय युवा शादी से भाग रहा है दूर

—उद्योग विहार (मई 2020)—

नई दिल्ली। यूगोव–मिंट–सीपीआर मिलेनियल सर्वे के अनुसार भारत में चार में से एक युवा शादी करने से कतरा रहा है। मिलेनियल उन लोगों को बोला जाता है जिनकी उम्र 23 से 39 साल के बीच है। सर्वे के अनुसार 19 फीसदी मिलेनियल को न तो शादी में रुचि है न ही बच्चों में। वहीं, आठ फीसदी मिलेनियल बच्चे तो चाहते हैं लेकिन शादी करना नहीं चाहते। वहीं, पोस्ट मिलेनियल यानि 23 साल से कम उम्र के युवा शादी और बच्चों में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। इन ट्रेंड में लिंग के अनुसार बेहद कम अंतर है।

आर्थिक असुरक्षा बन रही चिंता का कारण

शादी न करने के फैसले का सबसे बड़ा कारण आर्थिक असुरक्षा है। जिन घरों की महीनेभर की कमाई 10 हजार से कम है, वहां 40 फीसदी युवा शादी नहीं करना चाहते। उच्च आय वाले घरों में (महीनेभर की कमाई 60000 से ज्यादा) 20फीसदी युवा शादी नहीं करना चाहते। सर्वे के अनुसार गरीबों की तुलना में अमीर युवाओं में बच्चों की

चाहत ज्यादा है। महामारी के दौरान किए गए इस सर्वे में भविष्य की अनिश्चितता के कारण ज्यादातर लोगों ने शादी और बच्चों में कम रुचि दिखाई है। इस सर्वे को 12 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ऑनलाइन कराया गया था। इसमें 184 शहरों के 10,005 प्रतिभागी शामिल हुए थे। यह सर्वे मिंट, यूगोव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा किया गया है।

जाति और वर्ग का शादी में प्रभुत्व

शादी के बाजार में जाति और वर्ग को अब भी बहुत प्रभुत्व है। जो लोग शादी करना चाहते थे उनमें से अमीर प्रतिभागियों ने अपनी स्तर के बराबर की आय, धर्म, वर्ग और भाषा वाला साथी पाने की इच्छा जताई। वहीं, गरीब प्रतिभागियों ने अपने ही जाति के साथी से शादी करने की इच्छा जताई।

सही जीवनसाथी न मिलने से परेशानी

ज्यादातर भारतीय युवा सही जीवनसाथी न मिल पाने के कारण शादी करने से कतरा रहे हैं। 30 साल से ऊपर की उम्र वाले युवाओं में शादी से दूर भागने की प्रवृत्ति 30 साल से कम उम्र वालों की तुलना में ज्यादा देखी गई है। कई सालों से साथी की तलाश करने वाले 30 साल से ऊपर के 35 फीसदी युवा अब शादी नहीं करना चाहते। सर्वे में शामिल 32 फीसदी मिलेनियल शाद. ीशुदा थे, वहीं 57 फीसदी अविवाहित थे। आठ फीसदी मिलेनियल रिश्तों में थे लेकिन शादीशुदा नहीं थे।

प्रेम विवाह की इच्छा ज्यादा

जो युवा शादी में रुचि रखते है उनमें से दस में से चार अरेंज मैरेज करना चाहते हैं। ज्यादातर युवा प्रेम विवाह करना चाहते हैं। सर्वे में यह भी देखा गया है कि प्रेम विवाहों की तुलना में प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अरेंज मैरेज को ज्यादा पसंद करती नहीं देखी गई। 49 फीसदी युवा महिलाओं का कहना था कि वे प्रेम विवाह करना चाहती हैं जबकि पुरुषों में यह संख्या 41 फीसदी थी।

सीबीएसई की तरह डीयू में परीक्षा क्यों नहीं

—उद्योग विहार (मई 2020)—

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा को लेकर छात्रों, विभागाध्यक्षों व शिक्षकों का विरोध जारी है। अब यह सवाल उठने लगा है कि अगर सीबीएसई 12वीं के लाखों छात्रों की परीक्षा कक्षाओं में करवा सकती है तो डीयू क्यों नहीं करा सकता। क्योंकि जिस तरह सरकार लॉक डाउन में छूट दे रही है बहुत संभावना है कि जल्द ही यातायात कुछ नियमों के साथ सामान्य हो जाएं। इस बीच लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन के छात्रों द्वारा किए गए सर्वे में अधिकांश छात्राओं ने यह माना है कि वह ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकती यही नहीं उन्होंने यह भी माना है कि घर रहने पर वह पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हैं और कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं तक भी उनकी पहुंच कम है। डीयू के कार्यकारी समिति के सदस्य राजेश झा का कहना है कि डीयू ने ओपन बुक परीक्षा कराने का जो निर्णय लिया है वह मनमाना निर्णय है। इसको लेकर न छात्रों से बातचीत की गई न शिक्षकों

से और न ही विभागाध्यक्षों से। इसकी व्यवहारिकता पर कोई चर्चा नहीं की गई। यह भी नहीं सोचा गया कि होली में अपने गांव गए छात्र न तो अपने साथ किताबें ले गए हैं और न ही वह सुविधा संपन्न हैं। ओपन बुक परीक्षा भी उनके लिए बिल्कुल नया कांसेप्ट है। इससे डीयू के शिक्षक अनभिज्ञ हैं तो छात्र कैसे देगा। सीबीएसई लाखों छात्रों की परीक्षा जुलाई में कराने जा रही है, डीयू के पास तो उससे कम छात्र हैं। हो सकता है तब तक यातायात सुचारू रूप से चलने लगे। छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर ओपन बुक परीक्षा की जल्दी क्यों है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
देश–विदेश
08
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, मई, 2020
P.

34 दिनों में 11 हस्तियों की हो चुकी है मौत, बॉलीवुड के लिए 'काल' साबित हो रहा है 2020

–उद्योग विहार (मई 2020)–

साल 2020 हमारे सामने काल की तरह खड़ा है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और दूसरी तरफ लगातार बॉलीवुड सितारे एक के बाद एक दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। संगीतक. ार वाजिद खान के निधन की खबर ने एक बार फिर सबको दुखी कर दिया। इस साल के अभी तक पांच ही महीने गुजरे हैं और कई सितारे मौत के मुंह में समा चुके हैं। पिछले 34 दिनों में ही 11 बड़ी हस्तियों का निधन हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि ये 11 हस्तियां कौन हैं...

इरफान खान : बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपने हुनर का जौहर दिखाने वाले अभिनेता इरफान खान का निधन 29 अप्रैल को हो गया था। साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। निधन से पहले तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए।

ऋषि कपूर : इरफान खान की मौत से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि अगले ही दिन 30 अप्रैल को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। वो कैंसर (स्मनामउपं) से पीड़ित थे। करीब एक साल तक उनका अमेरिका में इलाज भी चला था लेकिन इसके बाद भी वो बीमारी से जंग नहीं जीत पाए। 24 घंटे से भी कम वक्त में दो अभिनेताओं का चले जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था।

योगेश गौर : 29 मई को बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गीत देने वाले गीतकार योगेश गौर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। योगेश की गिनती उन गीतकारों में होती थी जिन्होंने

अपने समय में सबसे बेहतरीन फिल्मकार रहे ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी आदि के साथ खूब काम किया था। उनके निधन से बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा था।

मोहित बघेल : मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन 23 मई को हो गया था। मोहित लंबे समय से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। उनकी उम्र सिर्फ 27 साल ही थी। मोहित ने सलमान खान, परिणीति चोपड़ा जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया था।

मनमीत ग्रेवाल : नवी मुंबई के खारघर इलाके में रहने वाले टीवी अभिनेता मनमीत ग्रेवाल ने 16 मई को खुदकुशी कर ली थी। 32 वर्षीय अभिनेता अपनी पत्नी के साथ किराए के फ्लैट में रहते थे। लॉकडाउन की वजह से टीवी सीरियल का काम बंद था ऐसे में वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे।

अभिजीत : शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के एक अहम सदस्य अभिजीत का निधन हो गया था। अभिजीत रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत से जुड़े थे। 15 मई को रेड चिलीज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। अभिजीत के निधन के बाद शाहरुख ने कहा था, हम सभी ने ड्रीम्ज अनलिमिटेड के साथ फिल्में बनाने की यात्रा शुरू की। अभिजीत मेरा सबसे अच्छा सहयोगी था। हमने कुछ अच्छा किया और कुछ गलत लेकिन हमेशा हम आगे बढ़े। वो टीम का मजबूत सदस्य था। तुम बहुत याद आओगे मेरे दोस्त।

सचिन कुमार : सीरियल 'कहानी घर घर की' के अभिनेता सचिन कुमार का 15 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। वो मुंबई के अंधेरी में रहते थे। 42 साल के सचिन अभिनेता अक्षय कुमार के कजिन लगते थे। बाद में सचिन ने अभिनय छोड़ फोटोग्राफी में अपना करियर बना लिया था।

अमोस : अभिनेता आमिर खान के असिस्टेंट अमोस ने 12 मई को अंतिम सांस ली। वो 60 साल के थे। अमोस करीब 25 साल से आमिर खान के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमोस के बहुत से करीबी लोग भी थे। अमोस की मौत हार्ट अटैक से हुई थी।

साई गुंडेवर : 'पीके' और 'रॉक ऑन' जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता साई गुंडेवर का 10 मई को अमेरिका में निधन हो गया था। साई पिछले एक साल से ब्रेन कैंसर से लड़ रहे थे। बॉलीवुड कलाकारों सहित महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अभिनेता को श्रद्धांजलि दी थी।

शफीक अंसारी : 10 मई को टेलीविजन के मशहूर अभिनेता शफीक अंसारी का निधन हो गया था। शफीक कैंसर से पीड़ित थे। शफीक ने 'क्राइम पेट्रोल' में विभिन्न किरदार किए। 52 साल के शफीक अंसारी ने मुंबई में अंतिम सांस ली।

कोरोना कहर के बीच भूकंप के झटकों से हिला नेपाल, रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.4 की तीव्रता

–उद्योग विहार (मई 2020)–

नई दिल्ली। कोरोना संकट के दहशत के बीच नेपाल में भूकंप आया है। नेपाल के भक्तपुर जिले के अनंतलिंगेश्वर इलाके में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नेपाल के अनंतलिंगेश्वर के पास सुबह करीब 8रू14 मिनट पर 3.4 की तीव्रता वाला भूकंप आया। अब तक इस भूकंप के झटके से किसी जान–माल को नुकसान की खबर नहीं मिली है। बता दें कि इससे पहले 15 मई को दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। लॉकडाउन में दिल्ली में चार बार भूकंप आ चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार यानी 15 मई को दोपहर 11 बजकर 28 मिनट पर कम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली के पीतमपुरा में था। यह भूकंप आठ किलोमीटर की गहराई में आया। इससे पहले 10 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम बदलने के बाद भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। उस दिन दिल्ली के कई इलाकों में आंधी–तूफान ने दस्तक दी थी। दिल्ली में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई थी। भूकंप के झटके के बाद कुछ इलाकों में लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए। कोरोना संकट के बाद से जब से लॉकडाउन लागू हुआ तब से दिल्लीवाले चौथी बार भूकंप के झटके महसूस कर चुके हैं। इससे पहले दिल्ली अप्रैल महीने में बैक टू बैक दो भूकंप का गवाह

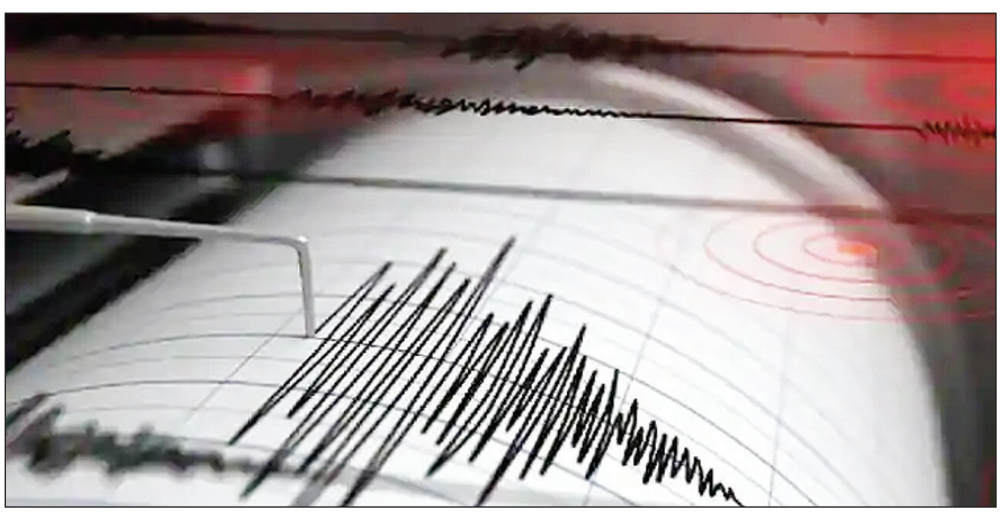

बना था। 13 अप्रैल को 3.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसकी गहराई दिल्ली एनसीआर में 8 किलोमीटर थी। ठीक उसी के अगले दिन यानी 14 अप्रैल को भी कम तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई थी।

भूकंप आए तो क्या करें

भूकंप के दौरान मकान, दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाएं। इसके बाद खुले मैदान की ओर भागें।भूकंप के दौरान खुले मैदान से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं होती।

भूकंप आने की स्थिति में किसी बिल्डिंग के आसपास न खड़े हों। अगर आप ऐसी बिल्डिंग में हैं, जहां लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ऐसी स्थिति में सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ही उचित होता है। भूकंप के दौरान घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें। इसके अलावा घर की सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें।

अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो और तुरंत उतर पाना मुमकिन न हो तो बिल्डिंग में मौजूद किसी मेज, ऊंची चौकी या बेड के नीचे छिप जाएं। भूकंप के दौरान लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पैनिक न करें और किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं, ऐसे में स्थिति और बुरी हो सकती है।

यूएई में कोविड–19 से मुकाबला करने के लिए भारतीय नर्सों ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कोविड–19 की महामारी से मुकाबला करने के लिए 88 भारतीय नर्सों के पहले दल ने मंगलवार (19 मई) को अपना मोर्चा संभाल लिया है। इस महीने की शुरुआत में नर्सों का यह दल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए भारत से यूएई पहुंचा। सभी नर्स केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के एस्टर डीएम हेल्थकेयर के अस्पतालों में कार्यरत थीं। यूएई पहुंचने के बाद करीब एक हफ्ते तक पृथकवास में रहने और कोविड–19 जांच की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इन नर्सों ने रविवार (17 मई) को परिचय कार्यक्रम के तहत हालात की जानकारी ली और मंगलवार (19 मई) को उन्होंने निर्धारित अस्पतालों में मिली नियुक्ति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करना शुरू किया। एस्टर डीएम हेल्थकेयर के संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निद. शक डॉ. आजाद मूपेन ने गल्फ न्यूज से कहा, श्श्इस दल की अधिकतर नर्सों की तैनाती दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण (डीएचए) के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में की जाएगी। डीएचए कुछ निजी अस्पतालों की भी मदद कर रहा है और जरूरत के हिसाब से इनकी तैनाती उन अस्पतालों में भी कर रहा है।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901/4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460/9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह